



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 234]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 8, 2016/आषाढ़ 17, 1938

No. 234]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 8, 2016/ASADHA 17, 1938

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

जांच शुरूआत

नई दिल्ली, 8 जुलाई, 2016

(निर्णायक समीक्षा)

**विषय :** चीन जन. गण. और यूएई के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 'ओपल ग्लासवेयर' के आयातों पर पाटनरोधी जांच की निर्णायक समीक्षा जांच की शुरूआत

**सं. 15/04/2016-डीजीएडी** -1995 में यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी कहा गया है) ने चीन जन. गण. और यूएई (जिन्हें आगे संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 'ओपल ग्लासवेयर' (जिसे आगे संबद्ध वस्तु कहा गया है) के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की थी।

2. यतः चीन जन. गण. और यूएई के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों से संबंधित मूल पाटनरोधी जांच की शुरूआत मै. ला ओपाला आरजी लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन के आधार पर दिनांक 26 अगस्त, 2010 की अधिसूचना सं. 14/24/2010-डीजीएडी द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकारी(जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) द्वारा की गई थी।

3. यतः मूल जांच में प्राधिकारी द्वारा प्रारंभिक जांच परिणाम जारी किए गए थे जिसमें 27 जून, 2011 की अधिसूचना सं. 14/24/2010-डीजीएडी द्वारा चीन जन. गण. और यूएई के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की गई थी। तदनुसार, 9 अगस्त, 2011 की अधिसूचना सं. 72/2011- सीमाशुल्क द्वारा चीन जन. गण. और यूएई के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर केन्द्र सरकार द्वारा अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था।

4. यतः मूल जांच में प्राधिकारी द्वारा अंतिम जांच परिणाम जारी किए गए थे जिसमें 25 अगस्त, 2011 की अधिसूचना सं. 14/24/2010-डीजीएडी द्वारा चीन जन. गण. और यूएई के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की गई थी। तदनुसार, 23 नवम्बर, 2011 की अधिसूचना सं. 103/2005- सीमाशुल्क द्वारा चीन जन. गण. और यूएई से आयातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर राजस्व विभाग द्वारा संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तु पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था।



### **समीक्षा हेतु अनुरोध**

5. यतः सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 1995 के अनुसार लागू पाटनरोधी शुल्क को यदि पहले न हटाया जाए तो वह उसे लगाने की तारीख से पाँच वर्षों के पूरा होने पर समाप्त हो जाते हैं।

6. और उक्त प्रावधान के होते हुए भी प्राधिकारी के लिए उपाय की समाप्ति की तारीख से पहले तर्कसंगत अवधि के भीतर घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से किए गए विधिवत रूप से साक्ष्यांकित अनुरोध के आधार पर इस बात की समीक्षा करना अपेक्षित है कि क्या शुल्क के समाप्त होने से पाटन और क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

7. और यतः उक्त प्रावधानों के अनुसार, मै. ला ओपाला आरजी लिमिटेड और मै. होपवेल टेबलवेयर प्रा. लि. (जिन्हें आगे 'याचिकाकर्ता कंपनियाँ' या 'आवेदक' कहा गया है) ने एक विधिवत रूप से साक्ष्यांकित आवेदन प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया है जिसमें संबद्ध देश के मूल की अथवा वहाँ से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर पहले लागू पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा करने और पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने का अनुरोध किया गया है। यह अनुरोध इन आधारों पर आधारित है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बावजूद संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहाँ से निर्यातित संबद्ध वस्तु का पाटन जारी है और संबद्ध देशों से पाटन के कारण घरेलू उद्योग को क्षति होना जारी है। आवेदक ने आगे यह तर्क दिया है कि यदि संबद्ध देश के विरुद्ध उपाय समाप्त हो जाते हैं तो पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

8. और, प्राधिकारी आवेदक द्वारा दिए गए प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर यह मानते हैं कि लागू पाटनरोधी शुल्क के लिए निर्णायक समीक्षा कार्यवाही की शुरुआत करना संबद्ध देश से पाटन की क्षतिपूर्ति करने के लिए ऐसे शुल्क को जारी रखने की जरूरत की जाँच करने और इस बात की जाँच करने के लिए उपयुक्त होगा कि क्या यदि शुल्क को हटाया या बदला जाता है तो घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

### **घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति**

9. यह याचिका मै. ला ओपाला आरजी लि. और मै. होपवेल टेबलवेयर प्रा. लि. (जिन्हें आगे घरेलू उद्योग या 'आवेदक' कहा गया है) द्वारा दायर की गई है और भारत में विचाराधीन उत्पाद का कोई अन्य ज्ञात उत्पादक नहीं है। याचिकाकर्ताओं का उत्पादन साथ मिलकर भारतीय उत्पादन का 100 प्रतिशत बनता है। याचिकाकर्ता पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) और नियम 5(3) की अपेक्षाओं को पूरा करते हैं और उनके पास नियमावली के अर्थ के भीतर वर्तमान याचिका दायर करने की योग्यता है और भागीदार कंपनियाँ घरेलू उद्योग हैं।

10. समीक्षा की जरूरत को सही ठहराते हुए घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सकारात्मक साक्ष्य के आधार पर स्वयं को संतुष्ट करते हुए, प्राधिकारी एतद्वारा पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 क (5) के अनुसार समीक्षा की शुरुआत करते हैं ताकि लगाये गए शुल्क का जारी रखने की समीक्षा की जा सके और इस बात की जाँच करने की जा सके कि क्या शुल्क के समाप्त होने पर पाटन और क्षति के जारी रहने या उनकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

### **विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु**

11. वर्तमान जाँच में विचाराधीन उत्पाद सभी प्रकार के ओपल ग्लासवेयर हैं (जिसे आगे संबद्ध वस्तु कहा गया है)। ओपल ग्लास एक दूधिया सफेद ग्लास होता है जिसका व्यापक रूप से लाइटिंग साज-सज्जा और टेबलवेयर में प्रयोग किया जाता है। इसमें प्रकाश को डिफ्यूज करने का गुण होता है जिससे ओपल ग्लासवेयर आकर्षक बन जाता है। सैंड/क्वार्टज, चूना, डोलोमाइट, ट्रोना, आर्थोक्लेस, बोरेक्स, अल्बाइट को ओपल ग्लासवेयर के विनिर्माण के लिए ओपल ग्लास के उत्पादन में प्रयोग किया जाता है। विचाराधीन उत्पाद को सामान्य भोजन, चाय, काफी परोसने, पकवान और सूप परोसने और स्नैक्स आदि परोसने के लिए प्रयोग किया जाता है।

12. प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि वर्तमान निर्णायक समीक्षा जाँच में विचाराधीन उत्पाद 'ओपल ग्लासवेयर' है। वर्तमान जाँच में विचाराधीन उत्पाद का दायरा पूर्व में अधिसूचित अंतिम जाँच परिणामों में विचाराधीन उत्पाद के दायरे के समान रहेगा।

13. ओपल ग्लासवेयर को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 के अध्याय 70 के अधीन उपशीर्ष 7013 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है तथापि सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जाँच के दायरे पर किसी भी तरह से बाध्यकारी नहीं है।

14. आवेदक ने दावा किया है कि आवेदकों द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से निर्यातित उत्पाद के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। दोनों उत्पादों में भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा टैरिफ वर्गीकरण आदि जैसे मापदंडों के अनुसार तुलनीय विशेषताएँ हैं। घरेलू उद्योग द्वारा यह दावा किया गया है कि घरेलू उत्पाद और आयातित उत्पाद के संबंध में अनिवार्य उत्पाद विशेषताओं की तुलना से पता चलता है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु अनिवार्य उत्पाद विशेषताओं की दृष्टि से संबद्ध देश से आयातित संबद्ध वस्तु के समान है। प्राधिकारी निर्धारित करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु संबद्ध देश से आयातित संबद्ध वस्तु के समान वस्तु है।



**प्रक्रिया**

15. इस जाँच से यह निर्धारित होगा कि क्या क्या उपाय की समाप्ति से पाटन और क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की आशंका है। प्राधिकारी इस बात की जाँच करेंगे कि क्या पाटन की क्षतिपूर्ति के लिए ऐसे शुल्क को जारी रखने की जरूरत है और क्या यदि शुल्कों को हटाया या बदला जाता है या ये दोनों किए जाते हैं तो क्षति होना जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

(i) इस समीक्षा में चीन जन. गण. और यूएई के संबंध में 25 अगस्त, 2011 की अधिसूचना सं. 14/24/2010-डीजीएडी के सभी पहलू शामिल होंगे। इस समीक्षा जाँच में शामिल देश चीन जन. गण. और यूएई हैं।

(ii) वर्तमान समीक्षा के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि अप्रैल, 2015 - मार्च, 2016 तक की अवधि है। तथापि, क्षति जाँच अवधि में अप्रैल 2012-मार्च 2013, अप्रैल 2013-मार्च 2014, अप्रैल 2014-मार्च 2015, और जाँच अवधि की अवधियां शामिल होंगी।

(iii) संबंधित नियमावली के नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 और 20 के उपबंध आवश्यक संशोधनों के साथ इस समीक्षा पर लागू होंगे।

**सूचना प्रस्तुत करना**

16. संबद्ध देशों में ज्ञात निर्यातकों, भारत में स्थित उसके दूतावासों के जरिए संबद्ध देशों की सरकारों, उत्पाद से संबंधित समझे जाने वाले भारत में ज्ञात आयातकों और प्रयोक्ताओं को निर्धारित प्रपत्र में एवं ढंग से संगत सूचना प्रस्तुत करने और निम्नलिखित पते पर प्राधिकारी को अपने विचारों से अवगत कराने के लिए अलग से लिखा जा रहा है:-

**भारत सरकार**

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय**

**वाणिज्य विभाग**

**पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय**

**चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग**

**5, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001**

**समय-सीमा**

17. वर्तमान समीक्षा से संबंधित कोई सूचना और सुनवाई हेतु कोई अनुरोध इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) के भीतर उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी के पास लिखित में भेजी जानी चाहिए। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अधूरी होती है, तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुसार, "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

18. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस समीक्षा जांच की शुरुआत की तारीख से 40 दिनों के भीतर वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और प्रश्नावली के अपने उत्तर दायर करें तथा पाटनरोधी उपाय जारी रखने की जरूरत अथवा अन्यथा के बारे में घरेलू उद्योग के आवेदन पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करें।

**गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना**

19. यदि प्रश्नावली के उत्तर/अनुरोधों के किसी भाग के बारे में गोपनीयता का दावा किया जाता है तो उसे दो अलग-अलग सैटों (क) गोपनीय रूप से अंकित (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि) और (ख) अगोपनीय रूप में अंतिम दूसरा सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि) में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। प्रस्तुत की गई समस्त सूचना पर प्रत्येक पृष्ठ के ऊपर स्पष्ट रूप से "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए।

20. किसी गोपनीय अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे। समस्त हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय रूपांतरण की दो (2) प्रतियां और अगोपनीय रूपांतरण की पाँच (5) प्रतियां सॉफ्ट प्रतियों के साथ, प्रस्तुत की जानी चाहिए।

21. गोपनीय रूप में दावा की गई सूचना हेतु; सूचना प्रदाता के लिए यह अपेक्षित है कि वह प्रदान की गई सूचना के साथ इस आशय के यथोचित कारण का एक विवरण उपलब्ध कराए कि ऐसी सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता और/अथवा ऐसी सूचना का सारांश क्यों संभव नहीं है।



22. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई/सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को समुचित ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है; तो प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांश क्यों संभव नहीं है।

23. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

24. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी रिकॉर्ड में नहीं ले सकते हैं। संतुष्ट होने और प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत को स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार का उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

### **सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण**

25. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।

### **असहयोग**

26. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

ए. के. भल्ला, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

## **MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**

### **(Department of Commerce)**

### **(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)**

### **INITIATION NOTIFICATION**

New Delhi, the 8<sup>th</sup> July, 2016

### **(Sunset Review)**

**Subject : Sun Set Review Initiation of Anti-Dumping investigation on imports of "OPAL GLASSWARE" originating in or exported from China PR and UAE.**

**No. 15/4/2016 – DGAD.**—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Designated Authority (herein after referred to as Authority) recommended imposition of Anti-Dumping Duty on imports of "Opal Glassware" (hereinafter referred to as subject goods) originating in or exported from China PR and UAE (hereinafter referred to as subject countries).

2. Whereas, the original anti-dumping investigation concerning imports of subject goods, originating in or exported from China PR and UAE, was initiated by the Designated Authority (hereinafter also referred to as the Authority) vide Notification No.14/24/2010-DGAD dated 26th August, 2010 on the basis of an application filed by M/s. La Opala RG Limited.

3. Whereas, in the original investigation, the preliminary finding was issued by the Authority recommending imposition of provisional anti-dumping duties on the imports of the subject goods, originating in or exported from China PR and UAE, vide Notification No.14/24/2010-DGAD dated 27th June, 2011. Accordingly, the provisional antidumping duties were imposed by the Central Government on the imports of the subject goods, originating in or exported from China PR and UAE, vide Notification No.72/2011-Customs dated 09th August, 2011.

4. Whereas, the final finding of the original investigation was issued by the Authority, recommending imposition of definitive anti-dumping duties, on the imports of the subject goods, originating in or exported China PR and UAE vide Notification No. 14/24/2010-DGAD, dated the 25th August, 2011. Accordingly, definitive anti-dumping duties on the subject goods imported from the subject countries was imposed by the Department of Revenue on subject goods imported from China PR and UAE vide Notification No103/2011-Customs, dated 23rd November, 2011.



**Request for Review**

5. Whereas, in terms of the Customs Tariff Act, 1995, the antidumping duty imposed shall unless revoked earlier, cease to have effect on the expiry of five years from the date of such imposition.

6. And, notwithstanding the above provision, the Authority is required to review, on the basis of a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry within a reasonable period of time prior to the date of the expiry of the measure, as to whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.

7. And, whereas, in terms of the above provisions, M/s. La Opala RG Limited and M/s. Hopewell Tableware Pvt. Ltd. (hereinafter referred to as 'petitioner companies' or "the applicants"), have approached the Authority with a duly substantiated application requesting for sunset review of the anti-dumping duty earlier imposed on the imports of the subject goods originating in or exported from the subject countries and seeking the continuation of anti-dumping duty. The request is based on the grounds that dumping of the subject goods originating in or exported from the subject countries has continued in spite of the imposition of anti-dumping duties on the imports of the subject goods from the subject countries and the domestic industry continues to suffer injury on account of dumping from the subject countries. The applicants have further argued that the expiry of the measure against the subject countries would be likely to result in continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

8. And, the Authority on the basis of prime facie evidence given by the applicants considers that initiation of sunset review proceedings for the anti-dumping duties in force would be appropriate to examine the need for continuation of such duties to offset dumping from the subject countries and to examine as to whether the injury to the domestic industry is likely to continue or recur if the duties were removed or varied.

**Domestic Industry & Standing**

9. The Petition has been filed by M/s. La Opala RG Limited and M/s. Hopewell Tableware Pvt. Ltd. (hereinafter referred to as the domestic industry or the applicants), and there is no other known producer of the product under consideration in India. The production of the petitioners together constitutes 100% of the Indian production. The petitioners satisfy the requirements of Rule 2(b) and Rule 5(3) of the AD Rules and the standing to file the present petition and the participating companies constitute "Domestic Industry" within the meaning of the Rules.

10. Having satisfied itself on the basis of the positive prima facie evidence submitted by the domestic industry substantiating the need for a review, the Authority hereby initiates the Sunset Review in accordance with Section 9 A (5) of the Act, read with Rule 23 of Antidumping Rules, to review the need for continued imposition of duties in force and whether the expiry of the duties would be likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.

**Product under Consideration and Like Article**

11. The product under consideration in the present investigation is Opal Glassware of all types (hereinafter referred as subject goods). Opal Glass is a milky white glass, widely used in lighting fixtures and tableware. It has a property of diffusing light, which makes Opal Glassware attractive. Sand/ Quartz, Lime, Dolomite, Trona, Orthoclase, Borax, Albite are used to produce opal glass for manufacturing opal glassware. The product under consideration is used for general eating, tea, coffee serving, pudding and soups serving, and serving snacks etc.

12. The Authority concludes that the product under consideration in the present sunset review investigation is "Opal glassware". The scope of the product under consideration in the present investigation remains the same as the scope of the product under consideration in the final findings earlier notified.

13. Opal Glassware is classified under Chapter 70 of Custom Tariff Act, 1975 under the sub-heading 7013. However, the customs classification is indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation.

14. The applicants have claimed that there is no known difference in product produced by the applicants and exported from the subject countries. Both products have comparable characteristics in terms of parameters such as physical & chemical characteristics, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification, etc. It has been claimed by the domestic industry that comparison of essential product properties in respect of domestic product and imported product show that the subject goods produced by the domestic industry are similar to the subject goods imported from subject countries in terms of essential product properties. The Authority determines that the subject goods produced by the domestic industry are like article to the subject goods imported from the subject countries.

**Procedure**

15. The investigation will determine whether the expiry of the measure would be likely to lead to a continuation or recurrence of dumping and injury. The Authority will examine whether the continued imposition of the duties is necessary to offset dumping and whether the injury would be likely to continue or recur if the duties were removed or varied, or both:-



- i. The review will cover all aspects of Notification No. 14/24/2010-DGAD, dated the 25th August, 2011 in respect of China PR and UAE. The countries involved in this review investigation are China PR and UAE.
- ii. The period of investigation for the purpose of the present review is from April 2015 - March 2016. The injury investigation period will however cover the periods April 2012-March 2013, April 2013-March 2014, April 2014 - March 2015 and the POI.
- iii. The provisions of Rules 6,7,8,9,10,11,16,17,18,19 and 20 of the Rule supra shall be mutatis mutandis applicable in this review.

#### **Submission of information**

16. The known exporters in the subject countries, the government of the subject countries through their embassies in India, the importers and users in India known to be concerned with the product are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority at the following address:

**Government of India**  
**Ministry of Commerce & Industry**  
**Department of Commerce**  
**Directorate General of Anti-Dumping and Allied Duties**  
**4th Floor, Jeevan Tara Building**  
**5, Parliament Street, New Delhi – 110001**

#### **Time Limit**

17. Any information relating to the present review and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 Days) from the date of publication of this Notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Anti-dumping Rules.

18. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses and offer their comments to the domestic industry's application regarding the need to continue or otherwise the Anti-dumping measures within 40 days from the date of initiation of this investigation.

#### **Submission of information on confidential basis**

19. In case confidentiality is claimed on any part of the questionnaire's response/submissions, the same must be submitted in two separate sets (a) marked as Confidential (with title, index, number of pages, etc.) and (b) other set marked as Non Confidential (with title, index, number of pages, etc.). All the information supplied must be clearly marked as either "confidential" or "non-confidential" at the top of each page.

20. Information supplied without any confidential marking shall be treated as non-confidential and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect any such non-confidential information. Two (2) copies of the confidential version and five (05) copies of the non-confidential version must be submitted by all the interested parties.

21. For information claimed as confidential; the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed and/or why summarization of such information is not possible.

22. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out /summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, parties submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summarization; a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.

23. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

24. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim may not be taken on record by the Authority. The Authority on being satisfied and accepting



the need for confidentiality of the information provided; shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

**Inspection of public file**

25. In terms of rule 6(7) of the Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidences submitted by other interested parties.

**Non-cooperation**

26. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

A. K. BHALLA, Addl. Secy. & Designated Authority